"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मार्च 2006—चैत्र 7, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 28 मार्च, 2006

क्रमांक-5082/विधान/2006.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 8 सन् 2006), जो दिनांक 28 मार्च, 2006 को पुर: स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 8 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2006

विषय सूची

भाग - एक

प्रारम्भिक

खण्ड :

भाग – दो

उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थानों
की स्थापना

भाग – तीन

सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवाशर्तें आदि

भाग – चार

सहायता अनुदान

भाग—पांच

वेतन सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में संस्थागत निधि, लेखों एवं वेतन भुगतान की प्रक्रिया

भाग — छः

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के बन्द होने पर सम्पत्ति एवं प्रबन्धन का अधिग्रहण

भाग – सात

सहायता – अप्राप्त महाविद्यालयों को तदर्थ अनुदान

भाग – आठ

विविध प्रावधान

* * * * * * * * * * * * *

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक ...8... सन् 2006)

छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2006

उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और कार्य प्रणाली के विनियमन को उपबन्धित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

भाग – एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 होगा ।

(2) यह उस तारीख से प्रभावशील होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

(3) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।

2. अधिनियम का लागू होना

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्ण या आंशिक सहायता प्राप्त करने वाले अथवा सहायता न प्राप्त करने वाले तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अवधारणा के अन्तर्गत एवं राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ में स्थित सभी अशासकीय महाविद्यालयों और / अथवा उच्च शिक्षा संगठनों पर यह अधिनियम लागू होगा ।

3. परिभाषाएं

इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(1) "तदर्थ अनुदान" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा किन्हीं विशेष उद्देश्यों के लिए प्रावधान के अन्तर्गत स्वीकृत राशि ;

(2) "सहायता प्राप्त महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत संधारण अनुदान के द्वारा नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त कोई भी महाविद्यालय या संस्थान ;

(3) "कॉलेज कोड" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22, सन् 1973) के परिनियम–28 में अन्तर्विष्ट प्रावधान ;

(4) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के द्वारा या अधीन विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार द्वारा समुचित रूप से संधारित या स्वीकृत शिक्षण, निजी सहायता या बिना

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं, जो महाविद्यालय या महाविद्यालय से भिन्न संस्थान, नाम की स्थापना से चलाये जा रहे हों, किन्तु जो स्वरूप, कार्यक्षेत्र, मापदण्ड से उच्च शिक्षा के महाविद्यालयों के धारणा के अधीन आती हों ;

(5) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, उच्च शिक्षा का आयुक्त अथवा वह अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे शासन द्वारा अथवा आयुक्त द्वारा अपनी ओर से शक्तियॉ प्रदान की गई हों ;

(6) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, जिसे शासन द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रयोजनों के लिए, अथवा ऐसे क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यों के निर्वहन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हों ;

(7) "शैक्षणिक एजेन्सी (अभिकरण)" से अभिप्रेत है, जब तक विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न हो, शैक्षणिक समिति, सोसायटी, ट्रस्ट या संघ, जो उच्च शिक्षा में आयोजित शैक्षणिक संस्था को प्रायोजित करता हो, उसकी देखरेख करता हो, प्रशासन करता हो, नियंत्रित करता हो अथवा चलाता हों

(8) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, अनुदान प्राप्त या अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा संस्था द्वारा नियोजित शिक्षण अथवा शैक्षणेत्तर स्टॉफ के सदस्य ;

(9) "संस्थापना समिति" से अभिप्रेत है, विधिवत् पंजीकृत एवं निगमित, पंजीकृत व्यक्तियों का निकाय या पंजीयन के लिए विधि द्वारा निगमित या शासकीय निगमन जिसकी निधि तथा संधारण ऐसे व्यक्तियों का समूह, जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में प्रविष्ट शैक्षणिक संस्था की स्थापना करता हो और जहां छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम, 1973 की धारा–33 के तहत् उस समिति का प्रशासी निकाय बर्खास्त कर दिया गया हो, वहां राज्य शासन द्वारा समिति की कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ;

(10) "सामान्य शिक्षा" से अभिप्रेत है, तकनीकी शिक्षा से भिन्न शिक्षा की सभी शांखाएं, जिनमें विशेष शिक्षा सम्मिलित ;

(11) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है, महाविद्यालय संहिता (कॉलेज कोड) के परिनियम क्रमांक–28 के प्रावधानानुसार गठित शासित निकाय ;

(12) "शासन" से अभिप्रेत है, जबतक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, छत्तीसगढ़ शासन ;

(13) "अनुदान" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा अकादमिक स्तर के उन्नयन, एवं संधारण तथा अधोसंरचना के लिए संधारण (वेतन) अनुदान, तदर्थ

को प्रदान किये जाने वाले वित्तीय अनुदान;

(14) "उच्च शिक्षा विभाग" से अभिप्रेत है, शासन के अधीन कार्यरत उच्च शिक्षा विभाग ;

(15) "निरीक्षण" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलेखों, पंजियों की छान–बीन तथा भवनों, ग्रन्थालयों, प्रयोगशालाओं, क्रीड़ांगन तथा अन्य सम्बन्धित मुद्दों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिर्धारित विशिष्ट भौतिक प्रविष्टियों के अनुसार जांच और शैक्षिक संस्था के विकास में शैक्षिक संस्थाओं तथा उसके कर्ता–धर्ताओं का समग्र मूल्यांकन ;

(16) "संस्था" से अभिप्रेत है, महाविद्यालय ;

(17) "संधारण / वेतन अनुदान" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा सहायता प्राप्त महाद्यािलयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्ते आदि के लिए नियमित रूप से दिया जाने वाला अनुदान ;

(18) "प्रबन्धन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सोसायटी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) के सन्दर्भ में उसका शासी निकाय तथा अभिव्यक्ति 'संस्था का प्रबन्धन' तद्नुसार व्याख्यायित होगी ;

(19) "अशासकीय महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण से परे व्यक्तियों के किसी समूह, ट्रस्ट या सोसायटी द्वारा प्रबन्धीकृत तथा संचालित महाविद्यालय ;

(20) "सहायता अप्राप्त महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय या संस्था की परिभाषा के अन्तर्गत न आने वाला महाविद्यालय ;

(21) "संस्थापना समिति का अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति, जो संस्थापना समिति द्वारा विधिवत् उसका अध्यक्ष (जिस नाम से पुकारा जाता हो) चुना गया हो और उसका कार्यकारी प्रमुख हो और यदि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के धारा–33 के तहत् समिति बर्खास्त की गई हो, तो राज्य शासन द्वारा समिति के कार्यों के देखरेख के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का मुखिया ;

(22) "शिक्षक" से अभिप्रेत है, किसी शैक्षणिक संस्था में शैक्षणिक स्टॉफ का कोई भी सदस्य, जिसे उस संस्था में शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया हो ;

(23) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय से है और कोई भी संस्थान उसमें समाहित है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 (में सन्निहित विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से परामर्शपूर्वक मान्य हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य की परिसीमा में कार्यरत हो ।

भाग — दो

उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना

4. इस अधिनियम की प्रावधानों की अनुकूलता से परे कोई भी शिक्षा—संस्था स्थापित नहीं की जायेगी और कोई व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है; अथवा जो इस धारा के अधीन प्रदत्त अनुमति को निरस्त किये जाने के बाद ऐसी संस्था चलाता है, उसे साधारण कारावास की सजा, जो छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो रूपये तीन हजार से कम नहीं होगा, किन्तु जिसे रूपये पचास हजार तक बढाया जा सकता है, से दण्डित किया जायेगा ।

उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना स्वीकृति के बिना नहीं होगी

5. शिक्षा देने वाली सभी संस्थाएं, जो कथित अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावशील होने के तत्काल पूर्व स्थापित एवं मान्यता प्राप्त थीं और इसके लागू होने के समय अस्तित्व में थी, उन्हें कथित अधिनियम के तहत् स्थापित एवं मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था माना जायेगा, बशर्ते कि वे कथित अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अन्तर्गत नियमों का अनुपालन ऐसी अवधि में और यथानिर्धारित ऐसी प्रक्रिया के अनुरूप पूरा करे, जैसे कि निर्धारित किया जा सकता है ;

विद्यमान संस्थाओं के लिए विशेष प्रावधान

परन्तु शिक्षा प्रदान करने वाले कोई भी निजी संस्था, जो कथित अधिनियम के लागू होने के समय अस्तित्व में हो, परन्तु इसके लागू होने के तत्काल पूर्व प्रभावशील नियमों के तहत् मान्यता प्राप्त न हो, कथित अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन रचित नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त करने आवेदन करेगी और ऐसे प्रत्येक आवेदन का निराकरण सक्षम अधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति के आठ दिनों की समयावधि के भीतर किया जायेगा ।

6. सक्षम प्राधिकारी समय—समय पर अपने अधिकार क्षेत्र में स्थान की शैक्षणिक आवश्यकताओं को जानने के लिए सर्वेक्षण करेंगे तथा निम्नलिखित के लिए अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त करने, निर्धारित रीति से स्थानीय समाचार पत्रों में अधिसूचना जारी करेंगे —

शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति

(क) शिक्षा प्रदान करने नई संस्था की स्थापना हेतु ; अथवा

(ख) उच्च शिक्षा की संस्था में उच्चतर कक्षाएं प्रारम्भ करने के लिए ; अथवा

(ग) नया पाठ्यक्रम (सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पाठ्यक्रम आदि) प्रारम्भ करने के लिए ।

7. अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन

महाविद्यालय खोलने की आकांक्षा रखने वाली ऐसी कोई भी समिति, जो "छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973" के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत हो, इस बारे में निर्धारित विधि से निम्नांकित प्रलेखों के साथ शिक्षा सत्र के पूर्व वर्ष के 31 अक्टूबर के पूर्व आयुक्त को आवेदन कर सकती है :–

(क) सोसायटी के पंजीयन का प्रमाण ।

(ख) प्रबन्धन एवं सम्बन्धित प्रबन्धकारिणी का विवरण ।

(ग) सोसायटी को उपलब्ध निधियों का उनसे सम्बन्धित प्रमाणों सहित विवरण

(घ) प्रसाधन, पानी तथा बिजली की मूलभूत सुविधाओं से युक्त कार्यालय, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, कॉमनरूम, खेल एवं क्रीड़ा आदि के लिए पर्याप्त स्थान वाले भवनों तथा भूमि का विवरण । स्वामित्व, अधिग्रहण या पट्टे की प्रलेखी प्रमाण भी प्रस्तुत किये जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, ऐसे प्रावधान कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए किये गये हैं ;

(ड.) संस्था चलानें के लिये आवश्यक अचल सम्पत्ति जैसे कार्यालय, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, कॉमन रूम आदि के लिए फर्नीचर एवं उपकरणों का विवरण ;

(च) निगमित निकाय का संविधान, जिसमें अनिवार्यतः उसके अन्य प्रावधानों के साथ प्रबन्धन एवं उसकी तथा प्रस्तावित संस्थाओं के प्रशासकीय और वित्तीय प्रबन्धन के विनियमों तथा परिनियमों प्रक्रियाओं का विवरण हो ;

(छ) प्रस्तावित आय एवं व्यय को दर्शाने वाले तीन वर्ष के अनंतिम बजट की प्रति ;

(ज) प्रस्तावित संकायों और कक्षाओं का विवरण ;

(झ) अर्जित भूमि और निर्माणाधीन भवनों के लिए अनुमोदित प्लान सहित सक्षम अधिकारियों की अनुमति ;

(ञ) प्रस्तावित स्थान के बीस किलोमीटर की परिसीमा में उच्च शिक्षा की सुविधाओं की उपलब्धता ;

(ट) प्रस्तावित क्षेत्र की परिसीमा में स्थित संस्थानों में प्रस्तावित विषयों की उपलब्धता ;

(ठ) साध्यता रिपोर्ट, यथा –

(एक) स्थान विशेष में जनता को उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता ।

(दो) संस्था की सतत् एवं प्रभावपूर्ण देखरेख के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पर्याप्त वित्तीय प्रावधान ।

(तीन) संस्था की अवस्थिति के लिए स्वच्छ स्वास्थ्यप्रद वातावरण ।

8. (1) जितनी कि निर्धारित की जाये, उतनी कायिक निधि (विन्यास) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संस्था की स्थापना के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा के द्वारा अनुमति प्रदान करने से पूर्व शैक्षिक अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी ।

कायिक निधि

(2) निजी संस्था की शैक्षणिक एजेन्सी अपनी प्रबन्धकारिणी शासन के प्रतिनिधि के रूप में उच्च शिक्षा के आयुक्त के संयुक्त लेखे में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में कायिक निधि जमा करेगी । जमा की गई कायिक निधि के आहरण की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी, तथापि शासन शैक्षणिक एजेन्सी को संस्था के विकास के लिए निर्धारित आधारभूत निधि के उपर उपार्जित ब्याज को पांच से दस वर्ष के अन्तराल में उपयोग में लाने की अनुमति दे सकता है ;

तथापि अपवादिक स्थितियों मे शैक्षिक–अभिकरण इस अन्तराल को घटाकर तीन वर्ष करने के लिए उच्च शिक्षा के आयुक्त से अनुरोध कर सकता है, तो भी किसी भी स्थिति में यह अवधि किन्हीं निर्धारित शर्तों के साथ तीन वर्ष से कम किसी हालत में नहीं होगी ।

9. शैक्षिक संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि और आवास स्थान का विस्तार विहित् अनुसार होगा । यह भी कि, शैक्षिक अभिकरण राज्य शासन द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप प्रस्तावित संस्थान के आवास के लिए सब उपयुक्त भवनों की व्यवस्था करेगा ।

उपलब्ध कराये जाने वाली भूमि और आवास स्थान का विस्तार

10. शैक्षिक–अभिकरण के पास अपनी खुद की जमीन पर खुद का स्थायी पक्का भवन होना अनिवार्य है । तथापि यदि ऐसा सम्भव नहीं है, तो शैक्षिक अभिकरण उच्च शिक्षा के आयुक्त से अनुरोध कर सकता है, जो निम्न कारणों को दर्ज करते हुए इसकी स्वीकृति दे सकता है :–

संस्थान के स्थल सम्बन्धी आवश्यकताएं

(क) यदि संस्था का स्थान–निर्धारण जिला पंचायत अथवा नगरपालिका से जुड़ी संस्था के परिसर के अन्तर्गत पंचायत अथवा नगरपालिका से, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तावित संस्था का स्थान–निर्धारण करे और पहले से स्थित संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं जैसे, भवन–संस्था की जगह, फर्नीचर, ग्रन्थालय, प्रयोगशाला, खेल–मैदान आदि का उपयोग पृथक जगह आदि उपलब्ध होने तक करने की पूर्वानुमति होगी । शैक्षणिक एजेन्सी संस्थाओं की स्थापना के लिए आवेदन सहित अनुमति के लिए पत्र प्रेषित करेगा एवं आवश्यक जगह एवं अन्य सुविधाएं यथाशीघ्र प्रस्तावित संस्था को पूर्णतः उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ;

तथापि, शैक्षणिक एजेन्सी के लिए यह अनिवार्य होगा कि, संस्था को चलाने के लिए पांच वर्ष के भीतर पृथक से जगह उपलब्ध कराये । शैक्षणिक संस्था द्वारा उक्त सुविधा नियत समय के भीतर उपलब्ध कराने में असफल होने पर संस्था चलाने हेतु दी गई अनुमति स्वतः-समाप्त मानी जायेगी । तथापि, यह शैक्षणिक एजेन्सी की विवेक पर होगा कि, वह रिक्त स्थान पर कौन सी संस्था चलाना चाहता है ।

(ख) यदि निजी संस्थान का स्थान–निर्धारण किसी निजी जगह में प्रस्तावित है, तो उच्च शिक्षा के आयुक्त शैक्षणिक एंजेन्सी को ऐसा करने की अनुमति दे सकते है, बशर्ते कि, संस्थाओं को जगह देने के लिए उपयुक्त पट्टे पर प्राप्त संस्था की इमारत अर्जित कर ली गई हो तथा कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए पट्टा प्रस्तुत कर दिया हो । शैक्षणिक एजेन्सी यह दर्शाने के लिए प्रलेखी प्रमाण भी प्रस्तुत करेगी कि, उनके पास चाही गई भूमि और निधि भवन निर्माण के लिए है और यह यथाशीघ्र नियत स्थान में कथित भवनों का निर्माण करने के लिए तैयार है ।

(ग) यदि निजी शैक्षणिक संस्था का स्थान–निर्धारण पहले से ही विद्यमान संस्था के परिसर में ही प्रस्तावित है, तो ऐसी शैक्षणिक एजेन्सी प्रस्तावित संस्था को उच्च शिक्षा विभाग और अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय के विनिर्देशन के अनुसार आवश्यक जगह तथा फर्नीचर, ग्रन्थालय, प्रयोगशाला आदि अन्य सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध करायेगी ।

(घ) यदि संस्था को दानदाता द्वारा प्रदत्त भवन में संस्थित किया जाना प्रस्तावित है, तो एतद् सम्बन्धी दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।

(ड.) यदि संस्था को ऐसी जगह में संस्थित किया जाना प्रस्तावित हो, जो पूर्व उल्लेखित खण्डों से परे है, तो उच्च शिक्षा के आयुक्त का निर्णय अंतिम माना जायेगा ।

(च) ऐसे शैक्षिक एजेन्सियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो निम्नलिखित क्षेत्रों में उच्च अध्ययन के संस्थान स्थापित करना चाहते हैं :–

(एक) ऐसे विकासखण्ड, जहां उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है

(दो) राज्य के दूरस्थ क्षेत्र, जहां पहुंचना सुगम नहीं है ।

(तीन) अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र, जहां किसी भी ओर शैक्षिक संस्थान स्थित नहीं है ।

(चार) जहां उच्च शिक्षा के अध्ययन की एक जगह से दूसरी जगह की भौतिक दूरी 30 किलोमीटर है, तथापि, अपवादिक प्रकरणों में यह दूरी घटाकर 20 किलोमीटर की जा सकती है ;

(पांच) आदिवासी विकासखण्ड, जहां अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है ।

(छः) ऐसे शहरी क्षेत्र, जहां जनसंख्या के घनत्व के लिहाज से उच्च शिक्षा के संस्थान नहीं हैं ।

(सात) जहां स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा में शिक्षा के प्रतिशत के विशेष सन्दर्भ में में शिक्षा का दर अत्यन्त कम है ।

(आठ) जहां शैक्षिक एजेन्सी द्वारा आदिवासी विकासखण्डों में आवासीय महाविद्यालय आरम्भ करने की योजना है ;

तथापि, आदिवासी विकासखण्डों में निजी अथवा जनभागीदारी योजना से आवासीय महाविद्यालय आरम्भ करने कोई भी शैक्षिक एजेन्सी शासन से सम्पर्क कर सकता है ।

निरीक्षण

11. सक्षम प्राधिकारी, आवेदन के विवरणों से संतुष्ट होने पर आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा के लिए प्रस्तावित संस्था के निरीक्षण हेतु, विहित रीति में विशेषज्ञों की एक समिति नाम निर्देशित करेगा । इस हेतु समिति दोनों पक्षों के सुविधाजनक तिथि पर विहित् शर्तों की पूर्ति की हद जानने, संस्थागत निरीक्षण करेगा तथा एक माह के भीतर अपने निष्कर्ष तथा अभ्युक्तियां देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि, स्वीकृति दी जाये अथवा नहीं । इसके साथ ही प्रतिवेदन में स्वीकृति देने पर या स्वीकृति देने के लिए विषयों, अध्ययन के पाठ्यक्रम, प्रवेश के लिए छात्रों की संख्या तथा शर्तें आदि कोई हों, का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा, जो यह नियत करेगा कि, अनुमति दी जा सकती है अथवा दिया जाय ।

अनुमति का प्रदाय

12. (1) अनुमति के प्रदाय की अनुशंसा सम्बन्धी प्रतिवेदन की प्राप्ति कर सक्षम अधिकारी अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेगा बशर्ते कि, उसके इस बात से संतुष्ट होने के कारणों परिस्थितियां न हों जिससे आवेदन की अस्वीकृति का औचित्य हो;

परन्तु अनुमति प्राप्त करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन से सक्षम अधिकारी भिन्न प्रस्ताव देता है, तो उसके लिए यह बाध्य कर होगा कि वह अमान्य करने के अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे ।

(2) अनुमति दिये जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी नियत समय में ऐसी शर्तें, जैसी कि, विहित की जाये, की पूर्ति के आशय को दर्शाते हुए पत्र जारी करेगा । तथापि यह किसी भी स्थिति में संबंधित वर्ष के संबंधित वर्ष के 31 मई से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा । सम्बन्धित शैक्षणिक एजेन्सी सक्षम अधिकारी को आशय पत्र में दर्शायी गई कमियों को पूरा करने विषयक सूचना देगा । आगे यह भी कि, उक्त एजेन्सी आगामी शिक्षण सत्र में संस्था प्रारम्भ करने हेतु अन्तिम निरीक्षण के लिए अनुरोध करेगा, उसके पश्चात् शैक्षिक संस्थान सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के बाद तत्काल सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्पर्क करेगा ।

(3) शैक्षिक एजेन्सी के द्वारा आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए समय में ढील दिये जाने सम्बन्धी निवेदन की स्थिति में इस प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति / व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिवेदन के उपरान्त ऐसा करना उच्च शिक्षा के आयुक्त के विवेक पर आश्रित होगा ।

तथापि, सक्षम अधिकारी कथित प्रयोजनों के लिये दी गई रियायतों से सम्बन्धित पूर्ति के प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त व्यक्ति / व्यक्तियों को निर्देशित करेगा और लगातार तीन वर्ष तक सन्तोषप्रद प्रगति नहीं पाये जाने पर सूचना जारी करते हुए प्रदत्त अनुमति वापस ले ली मानी जायेगी ।

13. उन्नयन के लिए अनुमति नहीं

उच्चतर माध्यमिक शाला का डिग्री कॉलेज के रूप में उन्नयन के द्वारा किसी शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी, तथापि, उच्च शिक्षा आयुक्त की पूर्वानुमति से विद्यमान संस्था परिसर में इस शर्त पर स्थापित की जा सकती है कि, शैक्षणिक एजेन्सी प्रस्तावित संस्था की श्रेणी अथवा कोटि के लिए विहित् आवश्यकताओं जैसे – स्थान, फर्नीचर, ग्रन्थालय, प्रयोगशाला और अन्य सुविधाएं अनन्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए तैयारी कर ली है ।

14. नये पाठ्यक्रम, संकाय और कक्षाएं आरम्भ करने हेतु आवेदन

नये पाठ्यक्रम, संकाय और कक्षाएं आरम्भ करने सम्बन्धी कोई आवेदन नव स्थापित संस्थाओं के आरम्भ होने की तिथि से तीसरे वर्ष के अंत तक विचारणीय नहीं होगा ।

तथापि, सक्षम प्राधिकारी आरम्भ होने की तिथि से तीन वर्ष पश्चात् प्रस्तावित अतिरिक्त अनुभागों अथवा पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक स्थान जैसी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होने की दशा में अतिरिक्त अनुभागों पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने की अनुमति दे सकता है ।

15. कतिपय प्रकरणों में विशेष प्रोत्साहन

सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा–10(च) के अधीन उद्धृत प्रकरणों में शैक्षिक एजेन्सी के आवेदन पर दिया जायेगा ।

(1) सामान्य प्रकरणों के लिए निर्धारित मानदण्ड से निर्धारित अचल सम्पत्ति

अथवा कायिक निधि के मूल्य पर 50 प्रतिशत की छूट जो शासन द्वारा अनुमति प्रदान करने की तारीख से तीन वर्ष अनधिक कालावधि के लिए ऐसें प्रकरणों में होगी, जहां –

(एक) प्रस्तावित संस्थान, अधिसूचित ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा हो ; और.

(दो) प्रस्तावित संस्थान के 20 किलोमीटर के दायरे में सामान्य या व्यवसायिक उच्च शिक्षा की संस्था न हो ।

तथापि, यह उल्लेखित छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन,संबंधित प्रबंधन समिति को किया जायेगा ।

(2) शासन, ऐसे आदिवासी विकासखंडों और अधिसूचित विकासखण्डों में जहां 50 किलोमीटर की दायरे में उच्च शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, शासन स्वयं या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सम्यक रूप से पंजीकृत निजी निकाय के स्वामित्व वाले विद्यमान उच्चतर माध्यमिक स्कूल के परिसर में नया महाविद्यालय आरम्भ करने अथवा चलाने के प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन रहते हुए विचार कर सकती है :–

(एक) स्थान, फर्नीचर और अन्य शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध हों ।

(दो) उपधारा–(1) में उल्लेखित विद्यमान संस्थान की अनुमति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत हो ।

(3) इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि, शैक्षिक एजेन्सी के पास सोसायटी के नाम कम से कम 15 एकड़ की पंजीकृत जमीन हो अथवा जनजातीय क्षेत्र में संस्थान प्रस्तावित होने पर सोसायटी के नाम कम से कम 05 एकड़ की पंजीकृत जमीन हो । शासन निम्नलिखित रियायतें देने पर विचार कर सकता है :–

(एक) लोक निर्माण विभाग / राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एजेन्सी के प्राक्कलन के अनुसार तथा निर्माण किये जाने वाले भवनों यथा प्रशासनिक भवन, क्लासरूम, छात्रावास क्रीड़ा परिसर एवं प्रयोगशाला पर कुल व्यय का 50 प्रतिशत अथवा रू10 लाख जो भी कम हो

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डों से नियुक्त शिक्षकों के वेतन हेतु अधिकतम रू.5 लाख जो आरम्भिक 10 वर्ष की अवधि के लिए अनिवार्य होगा ;

(तीन) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उपकरणों के क्रय की लागत का

50 प्रतिशत अथवा एक बार रू. 2 लाख जो भी कम हो;

(चार) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की सुसंगत पाठ्य पुस्तकों की क्रय लागत पर 100 प्रतिशत अथवा एक बार रू. 2 लाख जो भी कम हो;

तथापि, उपर्युक्त रियायतें ऐसी संस्था के लिए नहीं होगी, जो परम्परागत पाठ्यक्रम चलाना चाहते हैं ।

आगे यह भी कि, स्थित संस्था के जिले के जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित एक समिति उपर लिखित रियायतों को नाम निर्देशित करेगी । प्रतिवर्ष ऐसी अनुवीक्षण समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर, वांछित रियायतें जारी की जायेगी ।

16. अनुमति प्राप्त संस्थाएं सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करेगी

शासन से अनुमति प्राप्त संस्थान अपनी, अकादमिक पाठ्यचर्या तब तक आरम्भ नहीं करेगा, जब तक सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त नहीं कर लेता ।

17. अनुमति के बिना सम्बद्धता नहीं

किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट विपरीत बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय, किसी संस्थान को उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति के अनुमोदन के बगैर सम्बद्धता प्रदान नहीं करेगा । यह भी कि, सम्बद्धता आदेश की एक प्रति सूचनार्थ उच्च शिक्षा के आयुक्त को प्रेषित करेगा ।

18. अनुमति प्राप्त संस्थाओं के स्थान परिवर्तन और स्थानांतर पर निर्बन्धन

(1) किसी विशेष क्षेत्र की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थान की अनुमति प्राप्त किसी भी संस्था को अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

तथापि, उसी दृश्यता में एक भवन से दूसरे भवन में संस्था के स्थानांतरण की अनुमति बेहतर जगह देने या अपने ही भवन में स्थानांतरण करने की अनुमति शासन की पूर्वानुमति से देय होगी ।

(2) संस्था का एक जगह से दूसरी जगह अनाधिकृत रूप से बदलाव, से संस्था को प्रदत्त अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के अपने आप वापस हो जायेगा ।

(3) जिस शैक्षिक एजेन्सी को संस्था स्थापित करने की अनुमति दी गई है, वह किसी भी परिस्थिति में अन्य शैक्षिक एजेन्सी को संस्था का हस्तांतरण नहीं करेगा ।

19. अनुमति का प्रत्याहरण

(1) जहां किसी संस्था का प्रबन्धन इस अधिनियम तथा उसके अधीन निर्मित किसी नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, वहां सक्षम प्राधिकारी कारणों को लेखबद्ध करते हुए तथा प्रबन्धन को ऐसे निरस्तीकरण अथवा कार्रवाई के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देते हुए संस्था की अनुमति को रद्द कर सकता है अथवा ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है, जो आवश्यक प्रतीत होता है ।

(2) जहां शासन का यह अभिमत है, कि शैक्षणिक संस्थान को दी गई अनुमति जनहित में निरस्त की जानी चाहिए, वहां ऐसी संस्था के प्रबन्धन को अभ्यावेदन करने के लिए एक माह की सूचना देकर व कथित संस्था को दी गई अनुमति अधिसूचना द्वारा निरस्त कर सकता है ।

(3) सक्षम प्राधिकारी, निजी शैक्षणिक संस्था को स्वीकृत की गई अनुमति को स्थायी रूप से अथवा किसी विशेष समयावधि के लिए, जैसा उचित प्रतीत हो, तब समाप्त कर देंगे, जब कोई संस्था, जिसमें स्थायी रूप से सम्बद्धता प्राप्त संस्था सक्षम प्राधिकारी के विचार से किसी भी शर्त की पूर्ति करने में असफल रही है ।

परीक्षा प्रणाली पर नियंत्रण

20. आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन अथवा अंशतः बाह्य या अंशतः आंतरिक मूल्यांकन का विनियमन नियमों के द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि, वह छात्रों के मूल्यांकन की विश्वसनीय एवं प्रभावशील पद्धति के रूप में बनायी जा सके ।

स्वरूप के परिवर्तन पर निर्बन्धन

21. किसी भी परिस्थिति में महिलाओं के संस्थान को सह–शिक्षा या बालकों के संस्थान या परस्पर परिवर्तन / इसके विपरीत बदलने की अनुमति नहीं होगी ।

प्रवेश का विनियमन

22. (1) विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए निर्धारित आवेदन तथा आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन में उस आदेश का विवरण अनिवार्यतः होगा, जिसके तहत् संस्था स्थापित की गई है ।

(2) विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का प्रवेश सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्धारित प्रवेश नियमों के अनुसार होगा ।

(3) विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं दिया जायेगा । संस्था के प्राचार्य प्रवेश नियमों के उल्लंघन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

शुल्क का ढांचा

23. (1) शासन द्वारा शुल्क के निर्धारण और ढांचे के विनियमन के लिए एक सात सदस्यीय समिति गठित की जायेगी, जिसका अध्यक्ष उच्च शिक्षा का आयुक्त, सदस्य सचिव, उच्च शिक्षा का अतिरिक्त संचालक होगा । एक सदस्य, प्रबन्धन का, महाविद्यालय का प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय का एक प्राचार्य, अशासकीय महाविद्यालयों से एक प्राचार्य तथा, शासन द्वारा शुल्क के ढाचे को विनियमित करने हेतु एक शिक्षाविद् का नाम निर्देशित किया जायेगा ।

स्थायी समिति शुल्क के ढांचे को निर्धारित करने की प्रक्रिया में संस्था को शासन द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहन को ध्यान में रखेगी ।

भूमि और भवन के वाणिज्यिक उपयोग पर निर्बन्धन

24. राज्य शासन के अनुमति के बिना भूमि और भवन के वाणिज्यिक उपयोग के जरिये आय की अनुमति नहीं होगी, जहां शासन ने चाहे जिस भी रूप में भूमि प्राप्त करने या

25. आय के उपयोग पर निर्बन्धन

विशिष्ट प्रयोजनों से उपार्जित निधि से प्राप्त किसी भी आय का उपयोग केवल सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए होगा और उसके किसी भी हिस्से को अन्यथा व्यय करने की अनुमति नहीं होगी अथवा व्यवसाय में लगाना मान्य नहीं होगा ।

तथापि, ऐसी निधि के अवशेष का उपयोग एतद् विषयक आवेदन पर वेतन सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की पेन्शन निधियों में कमी को पूरा करने के लिए या सहायता अप्राप्त महाविद्यालयों में नियमित शिक्षकों के वेतन में कमी को पूरा करने के लिए आयुक्त द्वारा अभिलेखों के निरीक्षण के पश्चात् अनुमति दी जा सकती है ।

26. स्थायी प्रकोष्ठ की स्थापना

उच्च शिक्षा संचालनालय में अशासकीय संस्थाओं से सम्बन्धित कार्यों के नियंत्रण हेतु अतिरिक्त संचालक की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी के अधीन एक स्थायी प्रकोष्ठ स्थापित किया जायेगा । इस तरह नियुक्त अतिरिक्त संचालक शुल्क ढांचे के लिए गठित स्थायी समिति का सदस्य सचिव होगा ।

भाग – तीन

सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और सेवाशर्तें आदि

27. शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती

संस्थान में शिक्षक अथवा अन्य कर्मचारी के पद पर भर्ती :–

(1) राज्य शासन की पूर्वानुमति से और कॉलेज कोड परिनियम क्र.–28 के प्रावधानों के अनुसार होगी ;

तथापि अनुमति हेतु आवेदन सम्बन्धित विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जायेगा ।

(2) संस्थान के द्वारा अपने खुद के संसाधनों से शिक्षकों की भर्ती किये जाने पर शासन को कोई आपत्ति नहीं होगी । किसी भी स्थिति में ऐसे पदों को शासन द्वारा पूर्व से ही स्वीकृत सामान्य पदों में पदांतरित नहीं किया जा सकेगा ।

28. पदोन्नति

सम्बद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय समय–समय पर कॉलेज कोड परिनियम क्र.–28 के प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों के स्थानन / पदोन्नति के मामलों में यथोचित कार्यवाई करेगा ।

तथापि, ऐसे स्थानन / पदोन्नतियां, आयुक्त, उच्च शिक्षा से पूर्वानुमोदन के अधीन होंगे जो आगे इस पर शासन के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेंगे । इस प्रयोजन के लिए गठित समिति में उच्च शिक्षा के आयुक्त द्वारा नियुक्त एक सदस्य होगा ।

29. विश्वविद्यालय प्रति तीन वर्ष में कम से कम एक बार इन सहायता प्राप्त संस्थान के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का पुनर्विलोकन करेगा तथा समय–समय पर ऐसे पुनर्विलोकन के परिणामों की जानकारी एवं सूचना शासन को देगा । — सेवा शर्तें

भाग – चार

अनुदान

30. (1) राज्य में निजी प्रबन्धन के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को आगे निर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्रत्येक स्थान एवं प्रत्येक संस्था की आवश्यकताओं पर आवश्यक विचार के बाद अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा । — अनुदान

(2) अनुदान इनके लिए मंजूर किया जा सकता है :–

(एक) सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान के वेतन एवं भत्तों का अनुरक्षण ।

(दो) भवन ।

(तीन) उपकरण या जमीन ।

(चार) अन्य सम्बन्धित प्रयोजन हेतु उस परिमाण में और उन सीमाओं तक तथा उन शर्तों पर जो शासन को उचित लगे ।

(3) अनुदान के सम्बन्ध में शासन का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

31. (1) संधारण अनुदान, एक आवर्ती अनुदान है, जो सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे कर्मचारियों (शिक्षकों सहित) के वेतन भुगतान के लिए है, जिनकी नियुक्ति अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग या मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की सहमति से हुई है । — अनुदान के प्रकार

(2) तदर्थ अनुदान, एक अनावर्ती अनुदान है, जो गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय को प्रदान किया जाता है तथा जो अस्तित्व में हों तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम निरन्तर पांच वर्षों से "अच्छे रिकार्ड" सहित सफलतापूर्वक संचालित हो रहा हो।

32. स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी, अशासकीय शैक्षिक संस्थाओं के लिए उपलब्ध अनुदान के लिए आवेदन पर विचार कर सकता है, बशर्ते कि :– — अनुदान हेतु आवेदन

(i) विशिष्ट अनुदान के लिए आवेदन करने वाली संस्था की पात्रता प्रभावशील रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक समिति के रूप में पंजीकृत है तथा अनुदान की पात्रता के लिए सम्बन्धित विधि के अन्तर्गत शासन द्वारा विधिवत् मान्यता प्राप्त है ;

(ii) तदर्थ अनुदान के मामले में संस्था कम से कम पांच पूर्ण वर्ष से अधिक समय में अस्तित्व में हो तथा चल रही हो तथा संधारण अनुदान के मामले में दस वर्ष से स्थापित हो ;

(iii) अनुदान के लिए आवेदन ऐसे प्रयोजनों के लिए है, जैसा कि, शासन ने प्रावधान किया है ;

(iv) अनुदान के लिए आवेदन किसी निश्चित् जाति, वंश या समुदाय पर आधारित किसी वर्ग विशेष के हित को बढ़ावा देने से न जुड़ा हो ;

(v) संस्था का ऐसा कोई पूर्ववृत्त न हो, जिससे उसे सहायता के लिए अयोग्य माना गया हो ;

(vi) संस्था में दर्ज और उससे लाभान्वित छात्रों की संख्या उतनी हो, जितनी कि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त समझी जाय ।

33. अनुदान के लिए प्रारूप और घोषणा

अनुदान की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में निर्धारित शासन को किया जायेगा, साथ में मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्धन के हस्ताक्षरयुक्त इस आशय की घोषणा हो :–

(I) कि, मान्यता एवं अनुदान की उन शर्तों का पालन किया जाता रहा है व किया जायेगा ,

(II) कि, संस्था के निरीक्षण हेतु सभी सुविधाएं, उसका खाता, पंजियां तथा इस प्रयोजन से सम्बन्धित अन्य अभिलेख जब भी वर्णित हो, प्रस्तुत कराये जायेंगे ,

(III) कि, इसके लिए निर्धारित सभी रिटर्न तथा रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

34. अनुदान हेतु संस्वीकृति दाता प्राधिकारी

ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जहां शासन का सन्दर्भ वांछित है, आयुक्त, उच्च शिक्षा, राज्य निधि से भुगतान हेतु अनुदान स्वीकृत करेंगे ।

35. वेतन पर सहायता अनुदान सम्बन्धी निर्बन्धन

अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए वेतन पर सहायता अनुदान केवल ऐसे पाठ्यक्रमों एवं विषयों तक सीमित होगा, जो उस सामान्य शिक्षा से ही सम्बन्धित है, जो शासकीय महाविद्यालयों में उपलब्ध हैं तथा जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है ।

तथापि, यदि सहायता प्राप्त महाविद्यालय विद्यमान पाठ्यक्रमों से पृथक् कोई अन्य नया पाठ्यक्रम आरम्भ करना चाहें तो इस प्रयोजन से जुटाये निजी संसाधनों से वे ऐसा कर सकते हैं ।

अंकेक्षण

36. शासन से सहायता प्राप्त कर रहे सभी संस्थाओं के खाते अंकेक्षण के अध्याधीन हैं और आयुक्त, प्रत्येक संस्था के सम्बन्ध में यह निर्णय लेने में स्वतंत्र है कि, ऐसा अंकेक्षण उसके विभाग के अंकेक्षकों से कराया जाय या बाहर से तथा ऐसा अंकेक्षण, कैसे, कितने और अन्तराल में कराया जाये । आयुक्त के द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों को सभी पंजियों तथा रिकार्डों, खाताबहियों आदि तक पूरी पहुंच रहेगी, जिन्हें अंकेक्षक अपने कर्तव्यों के संतोषजनक निर्वहन परिशीलन किये जाने हेतु आवश्यक हो ।

अनुदान को रोकने, वापस लेने, निलम्बित करने, कम करने अथवा वसूली करने का अधिकार

37. अधोलिखित स्थितियों में आवश्यक जांच के पश्चात् शासन, संस्था को स्वीकृत अनुदान को रोक, वापस, निलम्बित, घटा सकता है अथवा आपत्ति के अधीन पायी गई राशि को वसूल सकता है और अनुदान से सृजित सम्पत्ति को शासन में निहित कर सकता है :-

(एक) यदि सम्बन्धित संस्था, मान्यता या सहायता के लिए सभी या किसी शर्त को पूरा करने में असफल होती है ;

(दो) यदि उस जाति या समुदाय के आधार पर किसी छात्र को प्रवेश देने से अस्वीकार करती है, जिसका कि, वह छात्र है, या.

(तीन) यदि प्रबन्धन या संस्था में नियुक्त कोई शिक्षक शासन के प्राधिकार के विरूद्ध निर्देशित राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेता है या छात्रों के मध्य समरूपता विरोधी भावनाओं या असंतोष की भावना को उकसाने को प्रवृत्त होने की धारणा मन में बैठाता है, या

(चार) यदि संस्था किसी धर्म के विश्वास और रिवाज के प्रति घृणा या तिरस्कार पैदा करने वाले प्रचार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ावा देता है, या

(पांच) यदि किसी शिक्षक के नियोजन के सम्बन्ध में आयुक्त के किसी आदेश की अवहलेना हो, जिसके प्रमाण--पत्र को नियमपूर्वक जांच के बाद निरस्त या निलम्बित किया गया हो, या किसी नियत जांच के बाद शिक्षक होने के अयोग्य या अवांछनीय पाया गया हो, या पंजियों में जालसाजी है या विशेष शुल्क संग्रहण या अन्य निधि का जिस प्रयोजन से संग्रहण किया गया है, उससे इतर दुरुपयोग किया गया हो या शुल्क अथवा उपस्थिति सम्बन्धि मिथ्या निरूपण हो या विश्वविद्यालय से सामूहिक नकल की सूचना हो. या अन्य प्रकरण या अन्य सिद्ध छल--कपट, अनियमितताएं पायी गई हों ; या

(छः) यदि कोई सम्बन्धित संस्थान, यू.जी.सी. वेतनमान और राज्य सरकार के अनुसार अपने शिक्षको एवं कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने में असफल रहता है अथवा जानबूझ कर शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशन का उल्लंघन करता है अथवा दर्ज छात्रों की संख्या सारणी के अनुसार पूरे किये गये

पाठ्यक्रम की जानकारी और निर्धारित प्रयोजनों के लिए प्रदत्त अनुदान के उपयोग का त्रैमासिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा के आयुक्त को प्रस्तुत करने में चूक करता है, या

(सात) यदि मुहैया कराये गये अनुदान का उपयोग, जिसके लिए मंजूर किया गया है, उससे इतर प्रयोजन के लिए किया गया है ।

38. अनुदान का व्यपगत होना

राज्य निधि से सहायता के प्रयोजन हेतु संस्था की पात्रता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, यदि संस्था की मान्यता वापस ले ली जाती है और ऐसी अपात्रता उसी तारीख से प्रभावशील होगी, जिससे मान्यता की वापसी प्रभावशील हुई है । इस शर्त के अध्यधीन कोई संस्था जो पूरे वित्तीय वर्ष में अथवा वर्ष के एक भाग में कार्य करती है, ऐसी कालावधि के लिए अनुदान की पात्रता होगी, भले ही उस कालावधि के बाद वह कार्य करे या न करे ।

भाग—पाच

वेतन सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में संस्थागत निधि, लेखों एवं वेतन भुगतान की प्रक्रिया

39. वर्तमान पद संरचना का संरक्षण

अधिनियम के आरम्भ होने से तत्काल पूर्व प्रवृत् किसी विधि के अधीन शासन से वेतन सहायता प्राप्त निजी संस्था में शासन द्वारा स्वीकृत अथवा शासकीय अनुमोदन से सृजित शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के पदों की विद्यमान संख्या को राज्य शासन की सहमति के बिना घटाया अथवा बढ़ाया नहीं जायेगा ।

40. शैक्षणिक संस्थाओं को दिया जाने वाले सहायता अनुदान बन्द नहीं किया जायेगा.

अधिनियम के इस भाग में या किसी अन्य भाग में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी निजी प्रबन्धन के अधीन कोई भी शैक्षणिक संस्था जो कि अनुदान के रूप में अधिनियम के आरम्भ होने से पूर्व किसी प्रचलित विधि के अधीन संधारण अनुदान के रूप में शासन से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही है, बिना किसी भी प्रकार की कटौती, चाहे जो भी हो, अथवा किसी कमी के बिना ऐसा सहायता अनुदान प्राप्त करना जारी रहेगा । बशर्ते धारा पांच के निर्धारित शर्तो का पूरा करता हो ।

व्याख्या — "संधारण अनुदान" या वेतन अनुदान का अर्थ तथा इसमें सम्मिलित है, राजय शासन द्वारा वर्तमान प्रावधानों के अधीन उनके वेतन, मंहगाई भत्ते इत्यादि के विरूद्ध प्रदत्त अनुदान ।

तथापि, स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन भी चलाये जाने वाले ऐसे विषयों, पाठ्यक्रमों एवं संकायों में कार्यरत शिक्षकों के लिए वही वेतनमान लागू होगा जो स्कूल शिक्षा विभाग के उन्हीं विषयों, पाठ्यक्रमों एवं संकायों के शिक्षकों के लिए लागू हैं, चाहे ऐसे विषयों, पाठ्यक्रमों एवं संकायों को आरम्भ करने की अनुमति सम्बन्धित महाविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग से ही प्राप्त की हो । यह प्रावधान, 01 नवम्बर, 2000 से प्रवृत समझा जायेगा ।

41. (1) ऐसे प्रकरणों में जहां वेतन अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धन के द्वारा शासन द्वारा अधिसूचित दर पर मंहगाई भत्तों का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया जाता, वहां आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा संस्था की वित्तीय स्थिति की जांच की जायेगी और ऐसे जांच के उपरान्त वह इस बात से संतुष्ट हो कि, प्रबन्धन शासकीय दर पर भत्ते के भुगतान के लिए सक्षम हैं तो वह सम्बन्धित प्रबन्धन को शासकीय दर पर भत्ते के भुगतान के लिए निर्देशित करेगा । — मंहगाई भत्ते का भुगतान

(2) यदि ऐसे निर्देश जारी होने के बाद राज्य निधि से अनुदान प्राप्त करने वाला प्रबन्धन शासकीय दर पर भत्ते का भुगतान नहीं करता है, तो उन्हें दिया जाने वाला अनुदान पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रोक सकता है ।

42. प्रत्येक ऐसी संस्था जो अनुदान प्राप्त है, एक या अधिक व्यक्तियों के प्रबन्धन के अधीन होगी, जिन्हें विभाग की मान्यता हो जो मालिक, न्यासी या संस्था का संधारण करने वाली सोसायटी या संघ द्वारा चुनी गई समिति के सदस्य की हैसियत में हो जिनके द्वारा संस्था का संधारण किया जाता हो, संस्था का संचालन करेंगें तथा संधारण के लिये उत्तरदायी होगें तथा ऐसे नियमों और अनुशासनों को जो समय –समय पर निर्धारित किये जाते हैं , को लागू करने सहित मान्यता एवं सहायता की समस्त शर्तो को पूरा करेंगे । — अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रबन्धन

43. जहां संस्था स्थित है, उस क्षेत्र में कोषालय या उप कोषालय में नियमों के अधीन प्रावधित लेखाशीर्ष में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के प्रयोजन के लिए प्रत्येक संस्था के द्वारा अपना पृथक खाता खोला जायेगा जिसमें संस्था की संस्थागत निधि को जमा किया जायेगा । — संस्थागत निधि का गठन

44. अधिनियम के अधीन शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रबन्धन द्वारा नामित संस्था के प्रतिनिधि तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा अथवा उसके द्वारा नामित द्वारा संयुक्त रूप से संस्थागत निधि का परिचालन किया जायेगा । कतिपय स्थितियों में जो कि राज्य शासन के नियमों के अधीन निर्धारित किये जा सकते हैं, आयुक्त अथवा उसके नामिती को आदेश में उल्लेखित अवधि के लिए एकल तौर पर संचालन के लिए अधिकृत किया जा सकता है । — निधि का परिचालन

45. (1) प्रत्येक संस्था के लेखा के पास–बुक का संधारण सम्बन्धित संस्था के द्वारा किया जायेगा, जो उसमें प्रविष्टि के लिए उसे प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में कोषालय या उप कोषालय भेजेगा । — पासबुक

(2) दिनांक 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए पासबुक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रेल माह के अंतिम सप्ताह में कोषालय या उप कोषालय भेजा जायेगा । 31 मार्च की स्थिति में बचत खाते का मिलान प्राचार्य अपने द्वारा संधारित लेखों से करेगा । यदि लेखों में कोई विसंगतियां पायी जाती है, तो कोषालय या उप कोषालय के लेखे से मिलान के

46. प्रत्येक शिक्षक और अन्य कर्मचारी दो खाते खोलेगा.

संस्था के ऐसे सभी शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी जो शासन एवं यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित सूची में वेतन सहायता के लिए दर्ज है, अपनी सुविधानुसार शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में वेतन भुगतान हेतु दो खाते खोलेंगे जिनमें से एक में उनका वेतन तथा दूसरे में भविष्यनिधि की रकम जमा की जावेगी । तथापि, प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी को अधिकाधिक प्रत्येक माह के अन्तिम दिवस तक और किसी भी परिस्थिति में आगामी माह की पांच तारीख तक वेतन भुगतान की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी । उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन की सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्यतः उच्च शिक्षा के आयुक्त को देनी होगी अन्यथा निर्धारित नियमों के अधीन प्रबन्धन के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई का कारण होगा ।

47 हस्ताक्षर के पूर्व देयकों की जांच

वेतन देयक और उस पर जारी चेक पर प्रबन्धन के तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकृत नामितों द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर परिवर्ती के द्वारा नियमानुसार सम्यक जांच के उपरान्त किये जायेंगे ।

संस्था के वेतन देयक में हस्ताक्षर से पूर्व उच्च शिक्षा विभाग का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुनिश्चित् करेगा कि, पूर्व माह में वसूले गये शुल्क का विवरण दो प्रतियों में संलग्न किया गया है और यह भी कि, कोषालय या उप कोषालय में इस खाते की जमा की जाने वाली निर्धारित राशि जमा कर दी गई है ।

चेक जारी करने से पहले उच्च शिक्षा विभाग के अधिकृत नामित द्वारा जांच के दौरान देयक अथवा चेक में त्रुटि पाये जाने पर तथा सूचित करने पर संस्था के द्वारा ऐसी त्रुटि /त्रुटियों को दूर किया जायेगा ।

48. शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन पर्ची का प्रावधान

शासन द्वारा नियत तिथि पर नियमानुसार प्राचार्य द्वारा प्रत्येक शिक्षक अथवा कर्मचारी को वेतन पर्ची दी जायेगी, जिसे वेतन मास का वैतन और भत्ते, वेतन से कटौतियां और बैंक खातों में जमा रकम दर्शायी जायेगी ।

49. शुल्क

अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट मानक दरों पर प्रबन्धन द्वारा वसूली गई शुल्क की कुल राशि का पचास प्रतिशत भाग संस्था के खर्चों को पूरा करने के लिए चिन्हित् होगा और शेष पचास प्रतिशत को निर्धारित नियमों के अनुसार समायोजन से अथवा चालान के जरिये प्रत्येक माह के अन्तिम दिवस तक कोषालय में अथवा उप कोषालय में जमा किया जायेगा ।

50. संस्था में रखी गई राशि के लेखे का पृथक से संधारण

शुल्क का पचास प्रतिशत हिस्सा कोषालय या उप कोषालय में जमा करने के बाद संस्था में रखी गई राशि का लेखा पृथक से संधारित किया जायेगा । इस लेखे के संधारण के लिए प्राचार्य उत्तरदायी होगा ।

51. लेखा पुस्तकों का संधारण

रोकड़ पुस्तिका, कोषालय चेक बुक और वेतन तथा शुल्क से सम्बन्धित खातों की पुस्तकें, प्रमाणक (व्हाउचर) तथा शुल्क से सम्बन्धित संस्था के कागजात, प्राचार्य की अभिरक्षा में रखे जायेंगे । लेखा के संधारण की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी और ऑडिट के समय लेखा से सम्बन्धित सभी पुस्तकों और अन्य कागजात को वह उपलब्ध करायेगा ।

52. राज्य निधि से अनुदान प्राप्त करने वाली प्रत्येक शैक्षणिक संस्था के लेखे का निरीक्षण और अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतिनियुक्त विभागीय अंकेक्षकों के द्वारा किया जायेगा । प्रबन्धन के द्वारा वित्तीय विवरण –पत्रक नियमों में निर्धारित सहपत्रों सहित प्रत्येक वर्ष के अनधिक मई माह के प्रथम दिन आयुक्त समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । **लेखा का वार्षिक अंकेक्षण**

भाग – छः

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के बन्द होने पर सम्पत्ति एवं प्रबन्धन का अधिग्रहण

53. कथित अधिनियम में विहित् प्रावधानों को छोड़कर अन्य कोई भी निजी संस्थान पूर्णतः या अंशतः बन्द या निरन्तरता क्रमबाधित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि, संगठन के अकादमिक वर्ष से कम से कम एक वर्ष पूर्व इस आशय की सूचना प्रबन्धन के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को नहीं दी गई हो । **बिना सूचना के अशासकीय संस्थान को बन्द आदि नहीं किया जायेगा**

54. संस्था के बन्द होने, निरन्तरता–क्रम बाधित होने या अनुमति एवं मान्यता को वापस लेने की स्थिति में प्रबन्धन संस्था उनके अधीन निहित सारी सम्पत्ति, सभी दस्तावेजों तथा लेखाओं को सक्षम प्राधिकारी को सुपुर्द करेगा या सुपुर्दगी करायेगा । **अशासकीय संस्थान के बन्द होने पर प्रबन्धन द्वारा सक्षम प्राधिकारी को सम्पत्ति इत्यादि के अभिलेख आदि को सौंपना**

55. (1) तत्समय प्रवृत किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निजी संस्था की किसी भी सम्पत्ति को बेचा नहीं जायेगा, बन्धक नहीं रखा जायेगा, पट्टे पर नहीं दिया जायेगा, गिरवी नहीं रखा जायेगा या अधिकार में परिवर्तन या निर्माण नहीं किया जायेगा सिवाय इसके कि, इस बारे में आवेदन करने पर सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति हो ; **अशासकीय संस्थान की सम्पत्ति के अन्य संक्रमण पर निर्बन्धन**

(2) (क) ऐसी स्थिति के सिवाय, जबकि उसकी राय में ऐसी स्वीकृति संस्था के कार्य करने पर विपरीत प्रभाव डालेगी, उपधारा–(1) में स्वीकृति के लिए किया गया आवेदन सक्षम अधिकारी के द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

(ख) सक्षम प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की समयावधि के भीतर स्वीकृति के लिए प्राथित आवेदन को स्वीकृत करते हुए आदेश पारित करेगा ।

(3) उपधारा–(2) के अधीन अस्वीकृति के आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति वैसी विधि से और उतने समय में जैसा कि, निहित् किया जाये, विहित अधिकारी को अपील कर सकता है ;

(4) उपधारा–(1) के विरूद्ध किया गया कोई भी लेन–देन अमान्य और विधि विरूद्ध माना जायेगा ।

56. अन्यसंक्रामण की अनुमति

शासन की ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा वह जारी कर सकता है, लिखित आदेशपूर्वक ऐसी भवन या भूमि के हस्तांतरण की अनुमति दे सकता है यदि:–

(1) हस्तांतरण शैक्षिक संस्था के प्रयोजनों के विस्तार या उससे जुड़े हुए आनुषांगिक प्रयोजनों के लिए जो शासन द्वारा अनुमोदित है तथा ऐसे हस्तांतरण से प्राप्त परिलब्धियों का उपयोग पूरी तौर पर कथित प्रयोजनों के लिए किया जाना है ;

(2) उपरिकथित प्रयोजनों के विस्तार के लिए हस्तांतरण केवल अंशतः किया गया है बशर्ते कि, शासन के द्वारा निर्देशित अनुसार ऐसे आंशिक हिस्से का भुगतान शासन को किया जाना है ;

(3) हस्तांतरण अन्य वैध कारणों से किया गया है, बशर्ते कि, इस कथित अधिनियम के अधीन प्रावधित अनुदान की पूरी राशि का प्रतिसंदाय शासन को किया गया है ।

57. कतिपय प्रकरणों के लिए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु प्रबन्धन का दायित्व

जहां कोई प्रबन्धनकर्ता ऐसी संस्था के प्रबन्धन के द्वारा प्रदत्त समुचित प्राधिकार के बिना संस्था को चलाने के निमित्त ऋण प्राप्त करता है और जहां सक्षम प्राधिकारी जांच के बाद यह पाता है कि, ऐसे ऋण के द्वारा प्राप्त रकमों का उपयोग संस्था के चलाने के लिए नहीं किया है वहां कथित ऋणों के भुगतान का व्यक्तिगत दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धनकर्ता का होगा ।

58. विवरणियों आदि को प्रस्तुत करना

प्रत्येक शैक्षणिक संस्था उतने समय में, या बढ़ाये गये समय जैसा कि, इस बारे में सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करे, सक्षम प्राधिकारी को वे विवरणियां, सांख्यिकीय आंकड़े और ऐसी अन्य सूचनाएं प्रस्तुत करेगी, जैसा कि समय–समय पर आवश्यक हो।

59. प्रवेश, निरीक्षण और सूचना प्राप्त करने का अधिकार

सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अध्याय में वर्णित किसी भी सम्पत्ति के अधिग्रहण या कब्जे के प्रयोजन से आदेशपूर्वक –

(क) अधिनियम के अधीन अधिग्रहीत किये जाने या कब्जे में लेने योग्य आदेश में विशिष्टीकृत किसी भी सम्पत्ति में प्रवेश करने और उसका निरीक्षण करने का अधिकार किसी भी प्राधिकारी को दिया जा सकता है ।

(ख) ऐसे प्राधिकारी के समक्ष किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार में निहित ऐसे किसी भी अभिलेख / सूचना को प्रस्तुत करने बाध्य किया जा सकता है जो आदेश में विशिष्टीकृत सम्पत्ति से सम्बन्धित हो ।

60 इस अध्याय के अधीन शैक्षणिक संस्था के प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के शासन में निहित पद वरिष्ठता, उन्मोचन, पदाभाव के कारण पदावनति, परिवीक्षाधीनों की पुनर्नियुक्ति और अनुमोदित परिवीक्षाधीनों तथा पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति के प्रयोजनों से एक पृथक इकाई होंगें ।

शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों के निहित पदों को इस अध्याय के तहत् कुछ उद्देश्यों के लिए एक इकाई माना जायेगा.

भाग – सात

सहायता – अप्राप्त महाविद्यालयों को तदर्थ सहायता अनुदान

तदर्थ अनुदान

61 तदर्थ सहायता अनुदान का तात्पर्य है, शासन की राज्य निधि से अलग वार्षिक अनावर्ती सहायता, जिसे उच्च शिक्षा के ऐसी मान्यता प्राप्त गैर–अनुदान संस्थाओं को नीचे निर्धारित शर्तों पर सहायता के योग्य पाए जाने पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए दिया जायेगा :–

(एक) भवन का विस्तार – विशेष रूप से शौचालय, सफाई–गृह, अध्ययन कक्ष, ग्रन्थालय, प्रयोगशाला भवनों, छात्रा–कक्ष और स्टॉफ रूम इत्यादि के लिए ;

(दो) शैक्षणिक अथवा तकनीकी प्रयोजन के तहत् उपकरण एवं यंत्र क्रय करने हेतु

(तीन) मूल सन्दर्भ के महत्व की पुस्तकों के क्रय हेतु ;

(चार) ग्रन्थालय के लिए रैक और आलमारी के क्रय हेतु ;

(पांच) कम्प्यूटर आधुनिक शिक्षोपकरण, शुद्ध जल की सुविधा प्रदान करने हेतु या जल आपूर्ति तथा नाली–पद्धति हेतु क्रय के लिए ;

(छः) कक्षाओं हेतु फर्नीचर के लिए ;

(सात) धारा 15 के (3) के अन्तर्गत प्रावधानित प्रयोजन हेतु ;

परन्तु अनुदान को नये महाविद्यालय की स्थापना हेतु निर्धारित मूल–शर्तों की पूर्ति हेतु नहीं दिया जायेगा तथा केवल विकासशील संस्था की वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग में लाया जायेगा ।

तदर्थ अनुदान हेतु पात्रता की शर्ते

62 आवेदन के इच्छुक संस्थान –

(क) ने संकाय के प्रथम वर्ष में प्रविष्ट छात्रों के सत्र से पांच वर्ष पूर्ण कर लिया हो ;

(ख) की छात्रों की संख्या –

(एक) शहरी क्षेत्रों के मामले में तीन सौ; से कम न हो

(दो) अनुसूचित क्षेत्र के, महिला महाविद्यालयों के, एवं ऐसे क्षेत्र जहां 25 किलोमीटर की परिधि में उच्च शिक्षा की ऐसी संस्था न हो, के प्रकरण में एक सौ पचास; से कम न हो

(ग) शैक्षणिक कर्मचारियों को यथासम्भव यू.जी.सी. वेतनमानों के अनुसार तथा गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों को शासकीय वेतनमानों के अनुसार वेतन प्रदान

(घ) सम्बन्धित महाविद्यालय शैक्षणिक, गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों दोनों के वेतन–पत्रक तदर्थ अनुदान की अर्हता के लिए प्रमाण की तरह प्रस्तुत करेगा ।

63. निरर्हता

कोई संस्था –

(क) जो इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों या किसी अन्य विधि का अनुपालन न कर पाये ;

(ख) विश्वविद्यालय या आयुक्त कार्यालय द्वारा, जिस पर सामूहिक नकल का दोषारोपण हो या अन्य प्रकार का कदाचरण जो संस्था की ख्याति को प्रभावित करता हो, तदर्थ सहायता अनुदान की पात्र नहीं होगी ।

64 प्राथमिकता

अनुदान पर विचार करते समय इन संस्थाओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी –

(क) जो अनुसूचित क्षेत्रों से ;

(ख) जो केवल महिलाओं की शिक्षा हेतु हों ;

(ग) जो ऐसे अधिसूचित विकासखण्ड से हो, जहां अभी तक उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं हो ;

(घ) जो प्रबन्धन में जन–निजी भागीदारी के अन्तर्गत स्थापित हो, और जिसमें संस्था की चल और अचल सम्पत्ति का कम से कम 30 प्रतिशत भाग जनता की अंशधारिता के रूप में हो ;

(ङ.) जो व्यवसायिक या अनुप्रयुक्त विषय और पाठ्यक्रम के पूर्ण सेटअप में स्थापित और संचालित हो ।

65. तदर्थ अनुदान की सीमाएं

(1) शासन अधिकतम 5 लाख रुपये तक अनुदान मंजूर कर सकता है जो इस शर्त के अधीन है कि, किसी एक मद के लिए 2 लाख रुपये से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसी संस्था, जिसे अनुदान स्वीकृत हुआ है, जब तक अनुदान स्वीकृति के तीन वर्ष पूर्ण नहीं कर लेती, अगले अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगी ।

(3) संस्वीकृति की राशि का निर्णय आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रस्तावित योजना की पात्रता और औचित्य के आधार पर विभाग या शासन करेगा ।

(4) अनुदान के आकार, स्वरूप एवं राशि के निर्णय का पूर्ण अधिकार शासन को होगा ।

(5) बिना कारण बताये आवेदन को अंशतः या पूर्णतः स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार शासन को होगा और ऐसा निर्णय अंतिम होगा ।

66. तदर्थ अनुदान हेतु आवेदन

कोई भी संस्थान शर्तों को पूरा करने की स्थिति में 31 अक्टूबर तक आयुक्त, उच्च शिक्षा को सम्बोधित करते हुए निर्धारित प्ररूप में तदर्थ सहायता अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है ।

तदर्थ अनुदान स्वीकृति पर उत्तरदायित्व

67. इस अधिनियम के उपबंधो के अध्याधीन :–

(1) क्रय करने हेतु शासन के भण्डार क्रय नियम, 2004 लागू किया जायेगा ।

(2) तदर्थ अनुदान की वस्तुओं के लिए अलग से पंजी बनायी जायेगी, जिसमें सभी खर्च का इन्द्राज आवश्यक रूप से अभिलेखबद्ध किया जायेगा ।

(3) तदर्थ अनुदान के व्हाउचर और सम्बन्धित अभिलेखों को अलग से रखा जायेगा तथा जब विभाग के संपरीक्षक (ऑडिटर) और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांगा जायेगा, तो उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा ।

(4) तदर्थ अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि के उपयोग अथवा खर्च को उन्हीं मदों तक स्वीकृत रखा जायेगा, जिन अनुमोदित योजनाओं / मदों की अनुमति आयुक्त, उच्च शिक्षा ने तदर्थ अनुदान स्वीकृत करते समय दी थी ।

(5) तदर्थ अनुदान से जो सम्पत्ति अर्जित की गई है, या उससे जो वस्तुएं खरीदी गई है, उनका शासन के प्राधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा ।

(6) तदर्थ अनुदान का उपयोग जिन मदों के लिए स्वीकृत किया गया है, उसे छोड़कर वेतन के भुगतान आदि या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा ।

(7) तदर्थ अनुदान के उपयोग के खर्च का विवरण संस्था द्वारा व्हाउचर और संपरीक्षित (ऑडिट किये हुए) खाता सहित स्वीकृत आदेश में अनुज्ञात उपयोग की अवधि की समाप्ति के तीन महीनें के भीतर आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजना होगा ।

(8) जो राशि या रकम खर्च करने से शेष है, उसे संस्था द्वारा शासन को इस धारा की उपधारा–(7) के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, तत्काल वापस किया जायेगा ।

भाग – आठ
विविध प्रावधान

नियम बनाने की शक्ति

68. (1) अधिनियम के किन्हीं या सभी प्रयोजनों को लागू करने के लिए शासन अधिनियम के द्वारा नियमों को बना सकता है ।

(2) विशेष रूप से और बिना पूर्ववर्ती उपधारा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम उपबन्धित किये जा सकते हैं :–

(एक) वह पद्धति, जिसमें इस अधिनियम के तहत् कोई जांच होगी ;

(दो) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित महाविद्यालयों के द्वारा पंजियों, विवरणों, प्रतिवेदनों और विवरणी, लेखों, आय–व्ययक एवं अन्य जानकारियों को संधारित या प्रस्तुत किया जाना ;

(तीन) शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना, संधारण और प्रशासन ;

(चार) शैक्षणिक संस्थाओं को अनुमति प्रदान करना और उसके लिए शर्तों का निर्धारण ;

(पांच) शैक्षणिक संस्थाओं में शुल्क की दरों, उगाही एवं संग्रहण का विनियमन करना ;

(छः) शैक्षणिक संस्थाओं में लेखा, पंजियों, आलेखों और अन्य दस्तावेजों के संधारण की पद्धति तथा ऐसे अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकृत व्यक्ति ;

(सात) शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निरीक्षण एवं वे अधिकारी, जिनके द्वारा निरीक्षण किया जायेगा ;

(आठ) ऐसी संस्थाओं के लेखा के रख–रखाव और अंकेक्षण की पद्धति;

(नौ) शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा और अध्ययन के पाठ्यक्रम का स्तर ;

(दस) छात्रवृत्तियों, वजीफों, शुल्क में छूट इत्यादि के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान की राशि के प्रावधान विषयक ;

(ग्यारह) सामान्य शिक्षा संस्थाओं के विकास की योजना तैयार करना । ऐसी योजनाओं की विषय सामग्री का निर्धारण तथा प्रस्तुत किया जाना ;

(बारह) उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी और अन्य अधीनस्थों के कार्यों एवं अधिकारों का निर्धारण ;

(तेरह) स्थानीय निकायों तथा निजी संस्थाओं के लिए भवन निर्माण की योजनाओं और प्राक्कलनों तथा भवन के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं की तैयारी तथा स्वीकृति विषयक ;

(चौदह) वे प्रयोजन जिनके लिए शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर का उपयोग किया जा सकता है तथा वे प्रतिबन्ध और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसे परिसरों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है ;

(पन्द्रह) शैक्षणिक संस्था में पाठ्य पुस्तकों, मानचित्र, योजनाओं, उपकरणों, प्रयोगशाला तथा खेलकूद के उपकरणों के उपयोग का विनियमन ;

(सोलह) शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों, असंस्थागत अध्ययन, अन्य विशेष पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा उपस्थिति का विनियमन इत्यादि ;

(सत्रह) अधिनियम के अधीन नियत अधिकारियों के द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यक अर्हताएं और अन्य शर्तें तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की पद्धति ;

(अठारह) संस्था के अन्तर्गत कक्षाओं और सत्रीय परीक्षाओं के परिचालन की पद्धति ;

(उन्नीस) वे शर्तें जिनके अधीन जनता से दान अथवा अंशदान, शैक्षणिक संस्था द्वारा स्वीकृत किया जा सके तथा संस्थाओं के नामकरण की नीति के सम्बन्ध में ;

(बीस) शैक्षणिक संस्थाओं में सह–शिक्षा की शर्तें एवं छात्रों के अनुशासन एवं आचरण सम्बन्धी विनियमन और अनुशासनहीनता तथा कदाचार के लिए दण्ड के सम्बन्ध में ;

(इक्कीस) सूचनाएं, आदेश तथा अन्य कार्यविधियों के प्रस्तुतीकरण की पद्धति और उनके सम्बन्ध में शुल्क तथा तद्विषयक कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का निर्धारण ;

(बाइस) किसी प्रमाण पत्र अथवा अन्य दस्तावेज, जिसके लिए शुल्क लिया जाना हो, के सम्बन्ध में भुगतान या शुल्क के निर्धारण की पद्धति के सम्बन्ध में ।

(तेइस) राज्य स्तर की शैक्षणिक परिषदों के गठन, उनकी संरचना और उनके प्रकार्यों का निर्धारण ।

(चौबीस) वे सभी विषय जो कथित अधिनियम की आवश्यकतानुसार निर्धारण के लिए प्रकटतः अनुज्ञप्त या वांछित है, या जिनके सम्बन्ध में अधिनियम में अपर्यापत प्रावधान है या प्रावधान का अभाव है, और जिस पर शासन की राय में कथित अधिनियम की समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे ।

शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण

69.(1) शासन या सक्षम अधिकारी किसी भी ऐसे अधिकारी को जो निरीक्षण के लिए निर्धारित स्तर से नीचे के पद का न हो, राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्था के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत कर सकता है ।

(2) उपधारा-(1) से प्राधिकृत अधिकारी शैक्षणिक संस्था की कार्यप्रणाली पर निरीक्षण के सामान्य अधिकारों का प्रयोग करेगा ।

(3) शैक्षणिक संस्था का प्रबन्धन और कर्मचारीगण सभी संगत-समयों पर ऐसी सहायता और सुविधाएं पूर्वोलिखित अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे जैसी कि, ऐसे निरीक्षण के लिए वांछित हो ।

(4) प्रबन्धक ऐसे निर्देशों अथवा सुझावों का अनुपालन करेगा जैसा कि, दिया गया है, बशर्ते कि, ऐसे निर्देशों व सुझावों से व्यथित प्रबन्धन ऐसे निर्देशों अथवा सुझावों की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर निर्धारित अधिकारी को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय ऐसी अपील पर अंतिम होगा ।

कतिपय प्रकरणों में नियमों की रचना

70. कथित अधिनियम के अधीन कोई भी नियम पूर्ववर्ती प्रभाव से बनाया जा सकता है और जब भी ऐसा नियम बनाया जायेगा तब एक वकतव्य से नियम बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जायेगा, जिसे कि, विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

71. शासन या किसी अधिकारी, प्राधिकारी या अधिनियम द्वारा या अधीन शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन के लिए संशक्त व्यक्तियों के विरूद्ध कथित अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों के अधीन सद्भावनापूर्वक किये गये या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी ।

72. निरसन तथा व्यावृति

तत्समय प्रवृत किन्हीं भी अन्य अधिनियमों, नियमों, आदेश में अन्तर्विष्ट किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी बात अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील होंगे :–

परन्तु अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना, प्रबन्धन तथा कार्यों को शासित करने वाले सभी अधिनियम तथा नियम जो अधिनियम के निगमन होने की तिथि पर प्रचलित थे, वे उच्च शिक्षा की विभिन्न श्रेणियों की अशासकीय संस्थाओं के सम्बन्ध में उस सीमा तक प्रभावशाली रहेंगे जिस सीमा तक वे अधिनियम के प्रावधानों को सम्पुष्ट करते हैं ।

73. इस अधिनियम के प्रावधानों से किसी भी संस्था को मुक्त करने की शक्ति

अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य शासन सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा ऐसी शर्तो के अधीन जैसा कि उसे आरोपित करना उचित प्रतीत हो अथवा इनके बगैर किसी संस्था या संस्थाओं की श्रेणी को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं प्रावधानों से मुक्त कर सकता है :

परन्तु ऐसे किसी भी आदेश में पूर्व उल्लिखित शर्त आरोपित करने या मुक्त करने के आधार का स्पष्टीकरण होगा ।

74. कतिपय राशियों की भू–राजस्व के शेष की तरह वसूली

अधिनियम के अधीन किसी भी संस्था के प्रबन्धन द्वारा जमा की जाने योग्य किसी भी राशि के निर्धारित अवधि में जमा नहीं किये जाने की अवस्था में ऐसी संस्था के प्रबन्धन से वह राशि उसी तरह वसूली जायेगी, जैसी कि भू–राजस्व के बकाये की वसूली की पद्धति है ।

75. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति

अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो शासन अधिनियम के प्रावधानों से अनसंगत आदेश द्वारा कठिनाई का निवारण कर सकता है,

परन्तु अधिनियम के आरम्भ होने से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ।

* * * * * * * *

उद्देश्यों और कारणों का कथन

चूंकि राज्य में शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना एवं कार्यप्रणाली को प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है, और वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान कानून अपर्याप्त हो गया है ।

अतः उपरोक्त प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित करने का निर्णय लिया है ।

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

अजय चन्द्राकर
उच्च शिक्षा मंत्री
भारसाधक सदस्य

रायपुर
तारीख 25/03/2006

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड क्र. 15(3) में प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के परिणाम स्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानित रुपये एक करोड़ मात्र का वित्तीय भार आयेगा ।

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

—

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के सम्बन्ध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2006 के खण्ड 68 के अधीन राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने कल शक्ति प्रत्यायोजित की गई है ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.